

## LOK SABHA DEBATES

I

LOK SABHA

Wednesday, April 12, 1978/Chaitra  
22, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of  
the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा  
नियुक्ति) विनियमों में संशोधन

\* 667. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या गृह  
मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपात काल के दौरान  
सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदो-  
न्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमों में किसी  
ऐसे संशोधन का प्रस्ताव किया था कि डिप्टी  
कलेक्टर से कलेक्टर के पद पर पदोन्नति  
के लिए योग्यता तथा बरिष्ठता के सिद्धान्त  
को खत्म करके केवल योग्यता/सक्षमता का  
सिद्धान्त अपनाया जायगा ,

(ख) क्या यह सिद्धान्त सरकार द्वारा  
स्वीकार किया गया था और जून, 1977 में  
प्रस्तावित किया गया था ,

(ग) क्या पदोन्नति के लिए योग्यता  
का सिद्धान्त अथवा योग्यता तथा बरिष्ठता  
का सिद्धान्त किसी राज्य की सेवाओं में  
अपनाया जाता है , और

(घ) क्या योग्यता के सिद्धान्त के  
परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी  
जहाँ एक ही जिले में बरिष्ठ अधिकारी  
कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन कार्य करेंगे

2

और क्या इससे अधिकारियों अथवा प्रशासन  
की कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं  
पड़ेगा ?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI S D PATIL) (a) and (b)  
Although action was initiated in 1974  
to amend the Indian Administrative  
Service (Appointment by Promotion)  
Regulations 1955, formal proposals  
were formulated on the recommenda-  
tions of the Chief Secretaries Con-  
ference held in May, 1976 The State  
Govts and UPSC were accordingly  
consulted and the regulations were  
amended in June 1977 by the present  
Government

(c) Information is not available  
with the Govt of India

(d) Such a situation is possible It  
could also have arisen under the  
regulations as they stood before the  
amendments made in June, 1977 As  
selections are made on the basis of  
merit Government do not think that  
this will adversely affect the efficiency  
of officers or the administration

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं  
सबसे महोदय से जानना चाहूंगा कि आपात  
काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने भारतीय  
प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति)  
नियम 1955 में यह संशोधन प्रस्तावित किया  
कि उप-जिला अधीक्षक को जिला अधीक्षक  
के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता तथा  
बरिष्ठता के सिद्धान्त का उन्मूलन कर सिर्फ  
योग्यता का सिद्धान्त माना जाय, यह इसलिए  
प्रस्तावित किया गया था कि मनवानी तौर  
पर योग्यता के नाम पर बरिष्ठ अधिकारियों  
को नजर-अन्वेषण किया जा सके और अपने

बहुते कनिष्ठ अधिकारियों को इस सिद्धांत का लाभ दिया जाये। मुझे बड़ा दुःख है कि इसी बात को हमारी सरकार ने जून 1977 में स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ है, मुझे दूसरे प्रान्तों की तो जानकारी नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं देता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसे सीनियर लोग जिनका यू-आउट रिकार्ड बहुत अच्छा था, जिन के खिलाफ कोई चीज नहीं थी उन को नजर भ्रन्दाज कर के ऐसे कई भ्रष्ट लोगों को जिन के खिलाफ बहुत सी चीजें थीं, कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दे दी गई। तो मैं मंत्री जी ने जानना चाहूंगा, मंत्री जी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो घपला हुआ है वह अन्य प्रान्तों में भी हुआ होगा, तो क्या वे उस की जांच कराएंगे ?

**SHRI S. D. PATIL:** No specific question has been put. However, Government has received a number of representations and the matter is under consideration of the Government.

**श्री सुखेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जब इन नियमों के तहत योग्यता के आधार पर मनमाने तरीके से यह सब किया जा रहा है तो क्या इन नियमों पर पुन विचार करके दोबारा संशोधन नहीं किया जा सकता है ? इसमें लोग मनमानी करते हैं, जो सीनियर और योग्य हैं, जिनका रिकार्ड अच्छा है उन्हें किनारे फेंक करके, जो उनके अपने चमके हैं जिनका रिकार्ड भी अच्छा नहीं है उन्हीं को मौका दिया जाता है। ऐसी स्थिति से क्या आप इन नियमों से संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ?

**SHRI S. D. PATIL:** I have already replied, the matter is under consideration

**श्री रघुबीर सिंह अज्जब :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या यह सच है कि जिन लोगों की पदोन्नति आपात

काल के समय की गई थी वे आज भी उसी पार्षों का काम कर रहे हैं ?

**SHRI S. D. PATIL:** The Government has no information. If the hon. member brings out any specific case, I will look into the matter.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** क्या यह सत्य है कि योग्यता और क्षमता के प्रतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाति और जन्म के आधार पर भी प्रमोशन हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

**MR. SPEAKER:** That does not arise.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** यह प्रमोशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

**MR. SPEAKER:** The question is about the rules—should it be solely on the basis of merit or merit-cum-seniority?

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** मैंने तथ्य जानने की कोशिश की है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

**MR. SPEAKER:** It is not between you and the 'mantri'. I also come into the picture.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** अध्यक्ष महोदय, योग्यता और क्षमता के आधार के प्रतिरिक्त जाति और जन्म के आधार पर प्रमोशन दिये जा रहे हैं।

**MR. SPEAKER:** It does not arise.

**SHRI JAGANNATH RAO:** At present the Central Government recruits IAS Officers and allots them to the State Government. Now the Regional Language has been introduced as a medium for examination. Is there any thinking to reverse the process? The State Government should recruit the officers according to the standards fixed by the Central Government and .

**MR. SPEAKER:** That again does not arise.